GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

DEPARTMENT OF FERTILIZERS

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO**. 85*** TO BE ANSWERED ON**: 30.07.2024**

PROMOTION OF ORGANIC FERTILISERS IN THE COUNTRY

85. SHRI SANDOSH KUMAR. P :

Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the details of Government policy to promote organic fertilizers in the country;

(b) the production of organic fertilizers in the country, State-wise;

(c) the use of organic fertilizers in the country, State-wise; and

(d) the impact of the use of organic fertilizers on yield and productivity?

ANSWER

MINISTER FOR CHEMICALS & FERTILIZERS AND HEALTH & FAMILY WELFARE

(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA)

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 85* FOR 30.07.2024 REGARDING – "PROMOTION OF ORGANIC FERTILISERS IN THE COUNTRY".

Government has been promoting use of organic & bio-fertilizers under various schemes viz. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP), Mission Organic Value Chain Development for North-East Region (MOVCDNER) and National Project on Organic Farming (NPOF). Under these schemes, farmers are encouraged to take up organic cultivation using organic inputs and the schemes provide end to end support to the farmers, i.e. from production to marketing of organic produce. Hands-on training to farmers about on-farm production of organic fertilizers and its use are integral part of these schemes. Farmers are provided a subsidy of Rs. 15,000/ha/3 years each under PKVY and MOVCDNER to make available organic inputs including bio-fertilizers and organic manure at affordable prices to the farmers.

Under Soil Health Card (SHC)/Soil Health Management (SHM) scheme Government is promoting Integrated Nutrient Management (INM) through judicious use of chemical fertilizers in conjunction with bio-fertilizers and organic manures for improving soil health and fertility.

National Project on Organic Farming (NPOF) is implemented under umbrella of Krishi Unnati Yojana's National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) through National Centre of Organic Farming (NCOF) with mandate to promote chemical-free farming that requires the use of bio/organic fertilizers.

Government has been providing assistance of ₹1,500/MT under the Market Development Assistance (MDA) scheme to promote marketing of organic fertilizers viz., Fermented Organic Manure (FOM), Liquid FOM, Phosphate Rich Organic Manure (PROM) produced at CBG/BG plants under GOBARdhan initiative. The scheme has a total outlay of ₹1,451.84 crore (FY 2023-24 to 2025-26), which includes a corpus of ₹360 crore for research gap funding etc.

Under MDA scheme, Fertilizer Companies have signed 31 Memoranda of Understanding (MoUs) with CBG plants for marketing of FOM, LFOM & PROM.So far, 2.98 Lakh Metric Ton of these organic fertilizers have been sold in total.

The State-wise production/consumption of Organic Fertilizers in India during 2022-23 is at **Annexure.**

Under All India Network Programme on Organic Farming (AI-NPOF) of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the evaluation of combined use of organic fertilizers, such as farm yard manure, composts (vermicompost, enriched composts etc.), bio-fertilizers and non-edible oilcakes is found to increase yield in certain crops like Soybean and desi cotton (Gossypium arboreum) by 1-8% in rainfed areas.

As per information provided by ICAR, Bio-fertilizers improved crop yields by 10-25% in different crops and therefore supplement costly chemical fertilizers (nitrogen and phosphorus) by nearly 20-25% in most of the cases when used along with chemical fertilizers. When bio-fertilizers are applied along with compost @ 5t/ha or vermi-compost @ 4t/ha, fertilizer saving will be upto 50%. Therefore, ICAR recommends integrated use of fertilizers and organic manures.

****

Annexure

State-wise production/consumption of Organic Fertilizers in India during 2022-23

S. No.	State	Total Organic Fertilizer in MT
1	Andhra Pradesh	2,72,572.13
2	Arunachal Pradesh	0
3	Assam	43,773.20
4	Bihar	53,256.38
5	Chhattisgarh	0
6	Delhi	0
7	Goa	11,221.37
8	Gujarat	2,78,036.86
9	Haryana	71,179.412
10	Himachal Pradesh	32.7965
11	Jammu & Kashmir	3,250.48
12	Jharkhand	0
13	Karnataka	22,78,241
14	Kerala	13,560.189
15	Madhya Pradesh	84,598.05
16	Maharashtra	2,37,843.28
17	Manipur	0
18	Meghalaya	0
19	Mizoram	0
20	Nagaland	0
21	Odisha	14,763.90
22	Punjab	7,407.06
23	Rajasthan	50,477.00
24	Sikkim	0
25	Tamil Nadu	2,31,522.00
26	Telangana	28,788.03
27	Tripura	946.81
28	Uttar Pradesh	74,799.23
29	Uttarakhand	7,440.451
30	West Bengal	6,704.806
31	Chandigarh	0
32	Puducherry	2,470.00
	Total	**37,72,884.40**

****

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **85***

जिसका उत्तर मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

देश में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाना

85*. श्री संदोष कुमार पी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की देश में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में जैविक उर्वरकों का राज्य-वार कितना उत्पादन होता है;
(ग) देश में जैविक उर्वरकों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) जैविक उर्वरकों के उपयोग का उपज और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"देश में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिये जाने" के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 85* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी), मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत ऑर्गेनिक और जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इन स्कीमों के तहत, किसानों को ऑर्गेनिक आदानों का उपयोग करते हुए आर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ये स्कीमें किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात आर्गेनिक उत्पाद के उत्पादन से लेकर विपणन तक की सहायता प्रदान करती हैं। ऑर्गेनिक उर्वरकों के ऑन-फार्म उत्पादन और इसके उपयोग के बारे में किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना इन स्कीमों का अभिन्न अंग है। किसानों को वहनीय कीमतों पर जैव उर्वरकों और आर्गेनिक खाद सहित विभिन्न आर्गेनिक आदानों के लिए पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर प्रत्येक के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) स्कीम के अंतर्गत सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार लाने के लिए जैव-उर्वरकों और ऑर्गेनिक खादों के मिले-जुले उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से समेकित पोषकतत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है।

केमिकल मुक्त खेती, जिसमें जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक होता है, को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) के माध्यम से कृषि उन्नति योजना के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कार्यान्वित किया जाता है।

सरकार गोबरधन पहल के अंतर्गत सीबीजी/बीजी संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों नामत: किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल एफओएम, फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) के विपणन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत ₹1,500/मीटन की सहायता उपलब्ध करा रही है। इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹1,451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए ₹360 करोड़ का कॉर्पस शामिल है।

एमडीए स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियों ने एफओएम, एलएफओएम और पीआरओएम के विपणन के लिए सीबीजी संयंत्रों के साथ 31 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, इन ऑर्गेनिक उर्वरकों की 2.98 लाख मीट्रिक टन की कुल बिक्री की गई है।

2022-23 के दौरान भारत में ऑर्गेनिक उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन/खपत **अनुलग्नक** में दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अखिल भारतीय ऑर्गेनिक खेती नेटवर्क कार्यक्रम (एआई-एनपीओएफ) के अंतर्गत ऑर्गेनिक उर्वरकों जैसे फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट (वर्मीकम्पोस्ट, समृद्ध कम्पोस्ट आदि), जैव-उर्वरकों और अखाद्य खली के मिले-जुले उपयोग के मूल्यांकन से पता चला है कि वर्षासिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन और देसी कपास (गॉसिपियम आर्बोरियम) जैसी कुछ फसलों की उपज में 1-8% की वृद्धि हुई है।

आईसीएआर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जैव उर्वरकों से विभिन्न फसलों में फसल पैदावार में 10-25% तक सुधार हुआ है और इसलिए जब इन्हें रासायनिक उर्वरकों के साथ उपयोग जाता है तो अधिकांश मामलों में महंगे रासायनिक उर्वरकों (नाइट्रोजन और फास्फोरस) की लगभग 20-25% तक की पूर्ति की है। जब जैव उर्वरकों को 5 टन/हेक्टेयर की दर से कम्पोस्ट अथवा 4 टन/हेक्टेयर की दर से वर्मी-कम्पोस्ट के साथ उपयोग किया जाता है, तो 50% तक उर्वरक की बचत होगी। अत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उर्वरकों और ऑर्गेनिक खादों के एकीकृत उपयोग की सिफारिश करती है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में ऑर्गेनिक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन/खपत

क्र.सं.	राज्य	कुल ऑर्गेनिक उर्वरक मीट्रिक टन में
1	आंध्र प्रदेश	2,72,572.13
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	43,773.20
4	बिहार	53,256.38
5	छत्तीसगढ़	0
6	दिल्ली	0
7	गोवा	11,221.37
8	गुजरात	2,78,036.86
9	हरियाणा	71,179.412
10	हिमाचल प्रदेश	32.7965
11	जम्मू और कश्मीर	3,250.48
12	झारखंड	0
13	कर्नाटक	22,78,241
14	केरल	13,560.189
15	मध्य प्रदेश	84,598.05
16	महाराष्ट्र	2,37,843.28
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	0
20	नागालैंड	0
21	ओडिशा	14,763.90
22	पंजाब	7,407.06
23	राजस्थान	50,477.00
24	सिक्किम	0
25	तमिलनाडु	2,31,522.00
26	तेलंगाना	28,788.03
27	त्रिपुरा	946.81
28	उत्तर प्रदेश	74,799.23
29	उत्तराखंड	7,440.451
30	पश्चिम बंगाल	6,704.806
31	चंडीगढ़	0
32	पुदुचेरी	2,470.00
	कुल	**37,72,884.40**

****

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA： Sir，how is the Government promoting the integration of organic fertilisers with the traditional and modern agricultural practices in Andhra Pradesh？Are there any pilot projects or partnerships with the local farmers to demonstrate the benefits and practical application of organic fertilisers？

MR．CHAIRMAN：Question Hour is over．